"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छ्त्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर,सोमवार, दिनांक 7 जनवरी 2019 — पौष 17, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, सोमवार, दिनांक ७ जनवरी, २०१९ (पौष १७, १९४०)

क्रमांक-212/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-(चन्द्र शेखर गंगराड़े) सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 1 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2019

वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की संचित निधि में से 1,03,95,58,25,400 रुपयों का दिया जाना. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2019 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दस हजार तीन सौ पनचानबे करोड़ अन्यवन लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची (धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान क संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनिधक राशियां			
			विधान सभा	संचित निधि	योग	
			द्वारा अनुदत्त	पर भारित		
(1)	(2)			(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये	
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	7,30,00,000	0	7,30,00,000	
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	95,00,000	0	95,00,000	
03	पुलिस	राजस्व	100	0	100	
		पूंजी	100	0	100	
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000	
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,23,54,85,100	0	12,23,54,85,100	
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित	राजस्व	2,50,200	0	2,50,200	
	व्यय					

(1)	(2)		(3)		
	e e		रुपये	रुपये	रुपये
10	वन	राजस्व	0	28,11,000	28,11,000
		पूंजी	12,00,00,000	0	12,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	32,90,00,000	0	32,90,00,000
13	कृषि	राजस्व	20,10,14,03,000	0	20,10,14,03,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	76,60,00,100	0	76,60,00,100
16	मछली पालन	राजस्व	24,27,000	0	24,27,000
17	सहकारिता	राजस्व	15,02,00,00,000	0	15,02,00,00,000
		पूंजी	98,00,00,100	0	98,00,00,100
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	5,75,90,40,000	0	5,75,90,40,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	300	0	300
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	राजस्व	0	14,52,000	14,52,000
	विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	60,00,00,000	0	60,00,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	6,76,21,00,000	0	6,76,21,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,53,90,000	0	1,53,90,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	28,07,43,33,200	0	28,07,43,33,200
		पूंजी	33,24,37,100	. 0	33,24,37,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	500	0	500
	2				3:

(1)	(2)	***************************************		(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	7,30,95,96,100	0	7,30,95,96,100
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यसंख्यक कत्याण	राजस्व	8,88,26,000	0	8,88,26,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	100	0	100
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	2,10,32,73,000	0	2,10,32,73,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	100	0	100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,16,37,00,000	0	2,16,37,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	70,47,00,000	0	70,47,00,000
		पूंजी	6,61,00,000	0	6,61,00,000
	योग -	राजस्व	1,02,13,80,24,900	42,63,000	1,02,14,22,87,900
	, Z	पूंजी	1,81,35,37,500	0	1,81,35,37,500
	वृहद योग		1,03,95,15,62,400	42,63,000	1,03,95,58,25,400

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी, 2019 श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री (भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

चन्द्र शेखर गंगराड़े सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा.